

सम्पादक के नाम

क्या सरकार के अन्यायपूर्ण, झूठी और गैरज़िम्मेदार होने की, गिरने की कोई हद भी होती है? पाखंड का एक उदाहरण!

22 अगस्त 2017 - हरयाणा सरकार का मेरे लिए तबादला आदेश : ओएसडी, लैंड यूज बोर्ड के नवसृजित पद पर।

13 अक्टूबर 2017 को चीफ सैक्रेट्री/हरियाणा सरकार से 6 सार्वजनिक सूचनाएँ माँगी गयीं-

- (एक) लैंड यूज बोर्ड के परिगठन की अधिसूचना
- (दो) बजट 2014-2015 से लेकर आज तक सालाना आंबटन
- (तीन) आहरण और वितरण प्राधिकारी बाबत सूचना
- (चार) ओएसडी/विभागाध्यक्ष के प्राधिकार,
- प्रकार्यकर्त्त्वों बाबत जानकारी
- (पाँच) बोर्ड के अमलेबाबत जानकारी (कितने-कौन?)
- (छः) बोर्ड के दफ्तरभवन का पता और वहाँ का फोननम्बर?

7 फरवरी 2018 को सरकार का लिखित जवाब-

- (एक) अधिसूचना दिनांक 21 9 2004 की प्रति।

- (दो) शून्य : कोई बजट नहीं।

- (तीन) शून्य : कोई बजट को संचालित करनेवाला और तनख्वाह निकालनेवाला नहीं।

- (चार) शून्य : कोई विभागाध्यक्ष/ओएसडी नहीं।

- (पाँच) शून्य : कोई अमला/स्टाफर्स नहीं।

- (छः) शून्य : कहीं कुछ नहीं। न कार्यालय, न फोन, न पता।

सब लापता।

22 अगस्त 2017 को कोई पद/विभाग नवस्वीकृत नहीं किया गया था, न प्रशासनिक/मन्त्रिमंडल के स्तर पर और न ही वित्त विभाग की हामी के साथ, और एक अश्लील, गंदा खड़ा झुट बोलकर ट्रान्सफर का वह आदेश निकाल दिया गया था, इसको भी दस्तावेज़ प्रदान करते हुए खुद सरकार ने स्वीकार किया है।

बहुत बाद में 22 अगस्त 2017 की तारीख में मीटिंग दिखाकर यह भी कहा गया कि यह पदस्थापन लोकप्रशासन की दृष्टि से अत्यावश्यक (administrative exigency) था और जनता के फायदे के लिये (in public interest) किया जाना आवश्यक था! !

× प्रदीप कासनी

मोदी जी द्वारा इस्लामिक विरासत का बखान.....

आयोध्या झाँकी है, 8 और बाकी हैं.....

जार्डन के किंग के भारत आगमन पर विज्ञान भवन में मोदी जी ने एक नए अंदाज में भाषण दिया और चार साल में पहली बार मुसलमान और भारत में इस्लामिक विरासत उंहें याद आई। क्या मोदी जी आरएसएस के हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा की जगह भारत की गंगा - जमुनी तहजीब में यकीन करने लगे हैं ? क्या उनका दृष्टिपरिवर्तन हो गया है ? इस मुद्दे पर बात करने से पहले आज की ही एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ पर गैर करते हैं। शिया वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चिठ्ठी लिखी है कि आयोध्या के अलावा अन्य 8 जगहें हैं जहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है इसलिए उन जगहों को ही हिन्दुओं को दे देना चाहिए।

फिर क्या था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन भर कार सेवा करता रहा। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी जगह हिन्दुओं की है और कौन सी मुसलमानों की। मैं तो सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी 2019 के लिए क्या - क्या नहीं कर रही है ? आज घाटी दोनों घटनाएँ मात्र इतेफ़ाक नहीं हैं बल्कि सोची समझी रणनीति है आरएसएस की।

छोटका (नीरव) मोदी से शुरू हुआ बैंकिंग घोटाला रोज अलग - अलग बैंकों में नए पते खोल रहा है। जिससे बीजेपी सरकार को काफ़ी राजनीतिक नुकसान हो रहा है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिये कुछ नया करने की जरूरत थी इसलिये एक मंच से मोदी जी मुस्लिम प्रेम के दोगली गीत गाते हैं, तो दूसरी तरफ शिया और सुन्नी को आमने सामने खड़ा कर मंदिर - मस्जिद के 8 अन्य मोर्चे खोल दिये जाते हैं। जिससे कि आने वाले समय में नए मोर्चों पर चुनाव लड़ा जा सकें।

आरएसएस के किचन में बने स्वादिष्ट राजनीतिक पकवानों को मीडिया बड़े ही शिद्दत से जनता के परोस रहा है। मीडिया पूरी तरह से मूल मुद्दों को छोड़ मोदी जी के प्रवक्ता और प्रोप्रैंडा अधिकारी के रूप में काम कर रहा है।

- शकीब रहमान

कहीं त्रिपुरा का हाल कश्मीर जैसा न हो!

त्रिपुरा में भाजपा का स्वतंत्र आधार नहीं रहा है। फिर भी वह क्यों जीत गई? कारण बड़ा साफ़ है। पहले वह सत्ता के भूखे कांग्रेस व तृष्णमूल कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपने साथ लाई। फिर उसने आदिवासियों के स्थानीय संगठन, इनडिजेनस पीपल्स फंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) को बहका लिया। त्रिपुरा में आदिवासियों के लगभग 35 प्रतिशत बोट हैं और इस बार एकमुश्त भाजपा गठजोड़ को पड़े हैं। यह अलग बात है कि इस गठजोड़ में 51 सीटें भाजपा ने खुद हड्डप लीं, जबकि केवल नौ सीटें ही भोले-भाले आदिवासियों के संगठन आईपीएफटी को दी हैं।

सबसे खतरनाक बात यह है कि आईपीएफटी सालोंसाल से त्रिपुरा के विभाजन के लिए संघर्ष करता रहा है। उसने आदिवासियों के लिए अलग तिप्रालैंड की मांग पर ही सारी गोलबंदी की है। अखंड भारत की बात करनेवाली भाजपा का राजनीतिक अवसराव इसी से साफ़ हो जाता है कि उसने त्रिपुरा में चुनावी जीत के लिए इस अलगाववादी संगठन से भी हाथ मिलाने में परहेज नहीं किया।

खैर, त्रिपुरा में लेफ्ट से सरकार छीनने का उसका मंसूबा अब पूरा हो गया है।

आशंका इसी बात की है कि कहीं त्रिपुरा का हश्त्र भी कश्मीर जैसा न हो जाए क्योंकि आईपीएफटी को अपने जनाधार को खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अन्यथा, अब तक शांत रहे सीमावर्ती राज्य त्रिपुरा में कश्मीर की पीड़ीपी-भाजपा सरकार के जैसे तनाव के बीच आदिवासियों का उबाल ज़ोर मार सकता है।

- अनिल सिंह

4-10 मार्च 2018

दूबने वाला है मोदी सरकार का अडानी को दिया 6200 करोड़ का लोन

मोदी सरकार ने अडानी को दिया था जनधन का पैसा, ऑस्ट्रेलिया में किया था अडानी ने इन्वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी योजना को ही किया रह।

अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में भी की थी नियमों की अनदेखी, इसलिए प्रोजेक्ट फंसे अधर में

गिरीश मालवीय

ऑस्ट्रेलिया में अडानी को कारमाइकल खदान के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अडानी समूह ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान, रेलवे और बंदरगाह परियोजना पर अरबों डॉलर से अधिक का निवेश कर चुका है।

उसे इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी जी ने भारतीय स्टेट बैंक से 6200 करोड़ का लोन दिलवाया था और वह भी तब जब 6 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण को खतरा बताते हुए फाइनेंस करने से मना कर दिया था। यह विदेशी धरती पर किये जाने वाले प्रोजेक्ट के लिए आज तक का सबसे बड़ा लोन था।

जिस वक्त यह लोन दिलवाया गया था, उसी वक्त जन धन योजना भी शुरू की गयी थी और उसी में जमा पैसों से स्टेट बैंक से यह लोन दिया है, जो अब डूबने की कगार पर आ गया है।

दरअसल, अडानी की रेललाइन परियोजना के तहत ऑस्ट्रेलिया में उसकी कारमाइकल खदान से लेकर ऐबट प्लाईट स्थित अडानी के स्वामित्व एवं उसके द्वारा परिचालित थोक कोयला लदान प्रतिष्ठान



तक करीब 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की योजना थी, जिसके वित्त पोषण के लिए चीन के 2 सबसे बड़े सरकारी बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया था।

बैंक का दावा है कि वह ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए प्रतिबद्ध है और इसे अहमियत देता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंक और वित्तीय संस्थान पहले ही लोन देने से मना कर चुके हैं। अडानी को आखिरी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया की सरकार से थी। 4 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से साफ़ इंकार कर दिया है।

इस निर्णय को ऑस्ट्रेलिया में अडानी के प्रोजेक्ट के लिए ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। भारत में अडानी का विभिन्न बैंकों का करीब 96,0×1 करोड़ का लोन बाकी है।

यह प्रोजेक्ट यदि डूबता है तो भारत पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही खतरे में आ जायेगी, क्योंकि अनिल अंबानी के रिलाय়ন्स ग्रुप पर भी लगभग 1,21,000 करोड़ का बैंड लोन है और चाइना डेवलपमेंट बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी आर-कॉम के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी का केस दर्ज करा दिया है।

रुद्धा के एस्सार ग्रुप की कंपनियों पर 1, 01,461 करोड़ का लोन बकाया है, जिसे वसूलने के असफल प्रयास किये जा रहे हैं। इन तथ्यों के आलोक में आप नीरव मोदी के पीएनबी घोटाले को रखकर देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक ह